(ख) राजस्थान में कितनी कपड़ा (काटन) मिलें और कितनी सूत मिलें हैं और उनमें से कितनी मिलें चल रही हैं और कितनी रुग्ण हैं ;

(ग) क्या राज्य में कपास की पैदावार को देखते हुए नई मिलों के स्थापित किए जाने की संभावना है, और यदि हां, तो कब तक और ऐसी नई मिलें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी, और

(घ) क्या राज्य में, भिवंडी की तरह विद्युत करघे लगाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) कपास मौसम 1991-92 के दौरान राजस्थान में कपास की 10.23 लाख गांठ का उत्पादन हुआ।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति अनुसार राजस्थान में 34 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (26 कताई मिलें + 8 मिश्रित मिलें) हैं तथा 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति अनुसार इनमें से 5 मिलें बंद पड़ी हुई हैं। 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति अनुसार राजस्थान में बी० आई० एफ० आर० द्वारा रुग्ण मिलों के रूप में सूचित की गई मिलों संख्या 12 है।

(ग) नई औद्योगिक नीति के अनुसार वस्त्र मिलों की स्थापना करने के लिए लाइसैंस लेना जरूरी नहीं है। तथापि, एन० सी० डी० सी० राजस्थान के गंगानगर जिले में 2 सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने पर विचार कर रहा है।

(घ) विद्युतकरघों की स्थापना विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होती है तथा यह निजी उद्यमियों द्वारा की जाती है। नए विद्युतकरघों की स्थापना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

Representation on the United Nations Commission on Sustainable Development

*137. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what steps Government have taken so far to get a berth on the proposed U. N. Commission on Sustainable Development, as a follow-up of the Earth Submit held in Rio;

(b) whether it is a fact that India has a better claim to get a representation because the country has a wide spectrum of competent Non-Government Organisations doing good work in this field as well as a large number of experts in Scientific field and eminent industrialists; as reported in the 'Hindustan Times' dated the 6th November, 1992; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (c) The structure and other modalities concerning the proposed Commission on Sustainable Development are yet to be finalised in the United Nations General Assembly. The exact manner of representation of any country in the Commission or its activities can be determined only in the light of that. But India's interest in being involved in this is known and will be taken forward when the modalities are finalised.

Allocation of Gas from HBJ Pipeline for Power Plants

*138. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleasd to state:

(a) whether the allocation of Gas from HBJ pipeline for power plants is based on any study justifying transportation of gas over long distances rather than evacuation of power; and

(b) if not, the reasons for not undertaking such a study ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) HBJ pipeline was originally conceived to supply gas to six fertilizer plants. Allocations for power plants were made subsequently